

एयर इंडिया का पुनः ‘‘राष्ट्रीयकरण’’ (नैशनलाइज़ेशन) करने की माँग उठने लगी है

रद्द उड़ानें, उड़ान भरने में बेवजह देरी आदि कारणों से यह छवि बन रही है कि एयर इंडिया में अब शीर्ष स्तर पर नागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन) के पर्याप्त अनुभव की कमी है

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 03 अगस्त। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी द्वारा टाटा समूह से एयर इंडिया को वापस लेने की सरकार से की गई मांग ने एक बार फिर उस बहस को ज़िंदा कर दिया है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि जनवरी 2022 में एयरलाइन के निजीकरण के साथ ही यह मामला सुलझ गया था। टाटा के नेतृत्व वाली एयर इंडिया के “प्रबंधन में गड़बड़ी” बताते हुए, तिवारी ने समूह पर राष्ट्रीय संपत्ति को कुप्रबंधन की मिसाल बनाने का आरोप लगाया, जिसमें उड़ान रद्द हो रही हैं समय पर उड़ानें नहीं मिल रही और विमानन क्षेत्र की समझ की कमी दिखाई दे रही है। तिवारी की निराशा पूरी तरह निराधार नहीं है। सोशल मीडिया पर यात्रियों की शिकायतें भरी पड़ी हैं, अनियमित समय-सारणी, खराब ग्राहक सेवा और व्यवस्थागत गड़बड़ियाँ। समूह द्वारा आधुनिक, और

- पर, क्या पुनः नैशनलाइज़ेशन करना इस समस्या का सही निदान है। क्योंकि एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपना एक “इमोशनल” निर्णय नहीं था, बल्कि आर्थिक विवशता दी। एयर इंडिया 60 हजार करोड़ रूपए का घाटा दे चुकी थी तथा सरकार के अनुदान के कारण घिसट रही थी। आशा की थी कि प्राइवेट हाथों में मैनेजमेंट जाने के बाद, यह घाटा रूकेगा तथा धीरे-धीरे एयर इंडिया चुस्त होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जायेगी।
- टाटा संस ने चुस्त बनाने की दिशा में कदम भी उठाये तथा सिविल एविएशन इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया नये हवाई जहाजों के लिए। स्टाफ के प्रशिक्षण के नये कोर्स शुरु किये गये तथा एयर इंडिया ब्राण्ड की विश्वसनीयता पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई। पर, यह काम वर्षों चलने के बाद रिजल्ट दिखाता है। अतः एक प्रतिक्रिया यह भी है कि अब पुनः नैशनलाइज़ेशन की बात करना न्यायोचित नहीं है।

यात्रियों के अनुकूल एयर इंडिया का जो वादा किया गया था, वह अब तक पूरी तरह हकीकत नहीं बन पाया है। लेकिन

उस एयरलाइन को फिर से अपने हाथ में लेना चाहिए, जिसे वह सालों तक सक्बिडी देकर भी चला नहीं पाई थी? पहले यह समझना जरूरी है कि एयर इंडिया का निजीकरण कोई आइडियोलॉजिकल फैसला नहीं था, बल्कि एक वित्तीय मजबूरी थी। यह एयरलाइन सरकार के लिए एक आर्थिक बोझ बन चुकी थी, 60,000 करोड़ से अधिक का नुकसान था, और सरकारी मदद से ही चल रही थी। करदाताओं का पैसा इस अनुत्पादक संस्था को बचाने में खर्च हो रहा था, जबकि वही पैसा स्वास्थ्य सेवा या बुनियादी ढाँचे में लग सकता था।

यह तो कहना पड़ेगा कि टाटा संस ने एक बहुत ही जटिल और संकटग्रस्त एयरलाइन संभाली है। चार एयरलाइनों (एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयरएशिया इंडिया) का एकीकरण कोई आसान काम नहीं है। टाटा ने विमानन इतिहास का सबसे बड़ा (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

उम्र कैद की सजा के खिलाफ रेवन्ना हाई कोर्ट पहुँचे

बेंगलु, 03 अगस्त। यौन शोषण के एक मामले में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) की ओर से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु के परम्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में कैदी नंबर दिया गया। इस बात की जानकारी रविवार (3 अगस्त, 2025) को जेल अधिकारियों ने दी।

प्रज्वल ने कथित तौर पर

- यौन शोषण के मामले में सांसद विधायकों की विशेष अदालत ने शेष जीवन तक कारावास की सजा सुनाई थी।

कर्मचारियों को सूचित किया है कि उसने अपनी सजा को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व सांसद फिलहाल उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में बंद है और उसे कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। प्रज्वल को शनिवार (2 अगस्त) को शेष जीवन तक कारावास में रहने की सजा सुनाई गई और कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि 11.25 लाख रुपये रेवन्ना के परिवार की घरेलू सहायिका व पीड़िता को दिए जाएं।

‘साढ़े छः लाख बिहारी श्रमिकों को तमिलनाडु का मतदाता बनाना अवैध’

चिदंबरम ने इसे तमिलनाडु के मतदाताओं के मनपसंद सरकार चुनने के अधिकार में हस्तक्षेप बताया

चेन्नई, 03 अगस्त। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों को भी मतदान का अधिकार देने का चुनाव आयोग का फैसला चिंताजनक और अवैध है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम तमिलनाडु के मतदाताओं के मनपसंद सरकार चुनने के अधिकार में घोर हस्तक्षेप होने के साथ-साथ प्रवासी श्रमिकों का भी “अपमान” है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में चिदंबरम ने कहा, “जहाँ बिहार में 65 लाख मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं तमिलनाडु में 6.5 लाख लोगों को मतदाता के रूप में जोड़ने की खबरें चिंताजनक और स्पष्ट रूप से अवैध हैं। उन्हें “स्थायी प्रवासी” कहना प्रवासी श्रमिकों का अपमान है और तमिलनाडु के मतदाताओं के अपनी नहीं लौटते, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं? क्या प्रवासी श्रमिक छठ पूजा के त्योहार के समय बिहार नहीं लौटते?

- चिदंबरम ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया रोजाना अजीब होती जा रही है। अगर प्रवासी मजदूर के परिवार का बिहार में स्थायी घर है तो उसे तमिलनाडु में “स्थायी प्रवासी” कैसे माना जा सकता है?”

प्रवासी श्रमिक जैसे छठ पूजा में वापस घर जाते हैं वैसे ही वे चुनावों में मतदान के लिए गृह राज्य क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, "प्रवासी श्रमिक विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए बिहार (या अपने गृह राज्य) क्यों नहीं लौटते, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं? क्या प्रवासी श्रमिक छठ पूजा के त्योहार के समय बिहार नहीं लौटते?

जब प्रवासी श्रमिक का बिहार (या दूसरे राज्य) में घर है तो उन्हें तमिलनाडु की मतदाता सूची में कैसे जोड़ा जा सकता है?" चिदंबरम ने कहा कि चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया रोजाना ही और भी ज्यादा अजीब होती जा रही है। अगर प्रवासी मजदूर के परिवार का बिहार में स्थायी घर है और वह बिहार में रहता है, तो उसे तमिलनाडु में “स्थायी प्रवासी” कैसे माना जा सकता है?" उन्होंने पोस्ट में लिखा, "चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और राज्यों के चुनावी चरित्र और पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रहा है। शक्तियों के इस दुरुपयोग का राजनीतिक और कानूनी विरोध करना चाहिए। विदित हो कि इससे पहले ड्रिविड मुनेत्र कथमग (द्रमुक) और उसके सहयोगी दलों ने राज्य में प्रवासी मजदूरों को वोट देने का अधिकार देने के चुनाव (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद होगी

नई दिल्ली, 03 अगस्त। भारतीय डाक विभाग ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें बताया गया है कि 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को अब स्पीड पोस्ट के साथ ही मिला दिया जाएगा। यानी अब ग्राहकों को पार्सल भेजने के लिए सिर्फ स्पीड पोस्ट की ही सुविधा मिलेगी। डाक विभाग ने बताया है कि इस फैसले के बाद पोस्ट सर्विस तेज और आधुनिक बनेगी।

- डाक विभाग, स्पीड पोस्ट सर्विस को तेज और आधुनिक बनायेगा।

सर्विस की सुविधा साल1854 में शुरू की गई थी। इसके जरिए ग्राहक जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ कीमती सामानों को भेजा करते थे। हालांकि अब 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्टसेलेबल नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस में ग्रूफ ऑफ डिलीवरी और रिसीवर के सिग्नेचर की जरूरत होती थी, जो अब ये स्पीड पोस्ट में मिलेगी।

आधिकारिक डाक डेटा 2011– (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

नागपुर, 03 अगस्त। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम को ये धमकी भरा कॉल आया है। इस कॉल के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार ,रविवार सुबह 8:46 बजे

- रविवार की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में बम से उड़ाने की धमकी का फोन आया था।
- नागपुर पुलिस ने गडकरी के घर पर डोंग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ घंटों में ही धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया। वह एक देशी शराब की दुकान पर काम करता है।

पुलिस कंट्रोल के 112 नंबर पर गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी का कॉल आने के बाद पुलिस ने स्थानीय पुलिस थाने को मामले की जानकारी दी है। कंट्रोल रूम को कॉल आने के बाद प्रताप नगर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

सरयू नहर में बोलेरो डूबी, 11 की मौत

मृतकों में गोंडा के सीहा गाँव के 3 भाईयों के परिवार के 9 सदस्य व दो पड़ोसी हैं

गोंडा, 03 अगस्त। यूपी के गोंडा में रविवार सुबह 10 बजे तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर सरयू नहर में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 भाइयों के परिवार के 9 लोग थे, जबकि 2 लोग पड़ोसी परिवार के थे। छोटे भाई का पूरा परिवार खत्म हो गया। ड्राइवर सहित 4 लोग बच गए। अभी 10 साल की बच्ची लापता है। एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश में जुटी है।

बोलेरो सवार 16 लोग जल चढ़ाने पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे। सभी गोंडा के मोतीगंज थाना के सीहा गाँव के रहने वाले थे। हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी नहर में गिरने के बाद एक भी शख्स बाहर नहीं निकल पाया। बारिश के कारण नहर में लबालब पानी भरा है। नहर में गिरते ही गाड़ी पूरी तरह से डूब गई। उसके गेट लॉक हो गए। अंदर बैठे

लोग छटपटाते रहे।

जानकारी के अनुसार, गाड़ी नहर के किनारे बनी सड़क से निकल रही थी। नहर क्रॉस करके जाना था। पुलिस के पास अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तेज स्पीड और बारिश की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर नहर में गिरने लगी। इस पर ड्राइवर गेट खोलकर कूद गया। आगे की सीट में बैठे 2 लोग भी बाहर आ गए। बच्ची पिंकी बीच में खड़ी थी। ड्टके से वह भी ड्राइवर साइड के गेट से बाहर आ गई। इसके बाद बोलेरो नहर में गिर गई।

जहां हादसा हुआ, वहां आसपास ग्रामीण मौजूद थे। बोलेरो नहर में गिरती देख वो लोग बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन गेट नहीं खोल पाए। रस्सी बांधकर बोलेरो को किनारे तक लाए, तब जाकर गाड़ी का कुछ हिस्सा बाहर (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

ग्रेनाइट खदान में बोल्ट्जर गिरने से 6 मजदूरों की मौत

बापतला, 03 अगस्त। आंध्रप्रदेश में बापतला जिले के बल्लीकुरवा गाँव में एक ग्रेनाइट खदान में रविवार को एक भारी शिलाखंड (बोल्ट्जर) गिरने से छह मजदूरों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गये।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मजदूरों का एक समूह सत्य कृष्णा ग्रेनाइट खदान में काम कर रहा था, तभी एक पहाड़ी से विशाल पत्थर लुढ़ककर उन पर गिर गया जिसमें छह मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गयी। अब तक चार शव बाहर निकाले जा चुके हैं और दो

- आंध्र प्रदेश में हुई दुर्घटना में चार अन्य मजदूरों की हालत नाजुक है।

को निकालने के प्रयास जारी है। जिस समय यह हादसा हुआ, तब ग्रेनाइट खदान में 16 मजदूर काम कर रहे थे।

इस हादसे में घायल अन्य मजदूरों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ चार मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रारंभिक जाँच के अनुसार, हादसे में मारे जाने वाले मजदूर ओडिशा के थे। (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से दो वोटर आईडी कार्ड पर जवाब मांगा

आयोग ने तेजस्वी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाये वोटर कार्ड की मूल प्रति मांगी

पटना, 03 अगस्त। बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियाँ जुटी हुई हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है और 2 वोटर आई कार्ड के संबंध में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के अनुसार, तेजस्वी यादव की प्रेस वार्ता के दौरान दिखाए गए इलेक्शन फोटो आईडेंटिटी कार्ड (ई.पी.आई.सी.) संख्या आरएबी 2916120 की जांच की जाएगी। आयोग ने तेजस्वी यादव से इसकी मूल प्रति मांगी है, जिसके लिए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की प्राथमिक जांच के अनुसार, तेजस्वी को ई.पी.आई.सी. कार्ड का

विवरण (कार्ड की मूल प्रति सहित) आयोग को उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। दरअसल तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी ने शनिवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने ई.पी.आई.सी. नंबर (आरएबी 2916120) को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सर्च किया, लेकिन नो रिकॉर्ड

- आयोग का कहना है कि जो कार्ड तेजस्वी ने दिखाया वह 10 साल से रिकॉर्ड में नहीं है तथा गत दो चुनाव तेजस्वी यादव ने जिस वोटर आईडी पर लड़े, वह दूसरा है।

तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मतदान केंद्र संख्या 204, क्रमांक 416 पर दर्ज है। उनका वैध ई.पी.आई.सी. नंबर आरएबी 0456228 है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया था कि तेजस्वी ने पीसी के दौरान जो ई.पी.आई.सी. नंबर आरएबी 2916120 दिखाया, वो पिछले

फाउंड का मैसैज आया। इसी बात को लेकर उन्होंने आयोग पर सवाल उठाए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने उनके दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि

बिहार एनडीए के घटक दलों के प्रवक्ताओं ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर सियासी हमला बोला। एनडीए प्रवक्ताओं ने दो ई.पी.आई.सी. नंबर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आया कहां से? कोई भी व्यक्ति दो मतदाता पहचान (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

10 साल में कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। जबकि तेजस्वी ने जिस ई.पी.आई.सी. नंबर आरएबी 0456228 के आधार पर 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े, वो आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद है।

बिहार एनडीए के घटक दलों के प्रवक्ताओं ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर सियासी हमला बोला।

एनडीए प्रवक्ताओं ने दो ई.पी.आई.सी. नंबर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आया कहां से? कोई भी व्यक्ति दो मतदाता पहचान (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

नोटिफाइड कीमतों की पालना नहीं करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

फॉर्मूले में एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, एमोक्सिसिल्लिन और पोटेशियम क्लैबुलनेट के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, एटोरवास्टेटिन कॉम्बिनेशन और एम्पैग्लिफ्लोजिन, सिटार्ग्लिटिन और मेटफॉर्मिन जैसे नए ओरल एंटीडायबिटिक कॉम्बिनेशन शामिल हैं।

नोटिफाइड कीमतों का पालन न करने पर डीपीसीओ, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं, जिसमें ब्याज सहित (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू से मिले

नई दिल्ली, 03 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात की वजह अभी सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में बताया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर चर्चा की विपक्ष की मांग को

- अभी तक इस मुलाकात का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है।

लेकर संसद में गतिरोध जारी है। साथ ही चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा के अलावा, मानसून सत्र शुरू होने के बाद से संसद में बहुत कम कामकाज हुआ है। राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की यह मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने और भारत के रूस से सैन्य उपकरण और तेल की खरीद के चलते पेनल्टी लगाने का भी एलान किया है।

सरकार ने 35 जरूरी दवाओं की कीमत घटाई

नई दिल्ली, 03 अगस्त। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब कई जरूरी दवाएं पहले से सस्ती मिलेंगी। सरकार ने 35 जरूरी दवाओं की कीमत घटा दी है, जिससे दिल, डायबिटीज, मानसिक रोग और इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के मरीजों को सीधी राहत मिलेगी।

ये फैसला रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एनपीपीए की सिफारिश पर लिया है। इसके तहत जिन दवाओं की कीमतें कम की गई हैं, वह लंबे समय से चल रही बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं।

प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले प्रमुख

- नोटिफाइड कीमतों की पालना नहीं करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

फॉर्मूले में एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, एमोक्सिसिल्लिन और पोटेशियम क्लैबुलनेट के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, एटोरवास्टेटिन कॉम्बिनेशन और एम्पैग्लिफ्लोजिन, सिटार्ग्लिटिन और मेटफॉर्मिन जैसे नए ओरल एंटीडायबिटिक कॉम्बिनेशन शामिल हैं।

नोटिफाइड कीमतों का पालन न करने पर डीपीसीओ, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं, जिसमें ब्याज सहित (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

मस्तिष्क इन्द्रियों की अपेक्षा महान है, शुद्ध बुद्धिमत्ता मस्तिष्क से महान है, आत्मा बुद्धि से महान है, और आत्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। –स्वामी शिवानंद

हमारे बच्चे और सोशल मीडिया

क्या आप जानते हैं कि हम भारतीय सोशल मीडिया का कितना प्रयोग करते हैं? शायद यह बात आपके लिए भी चौंकाने वाली हो कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम भारतीय ही करते हैं। हमारे यहां एक व्यक्ति औसतन 1१ प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहता है और हर दिन लगभग 7.3 घण्टे स्क्रीन पर (मोबाइल या अन्य) व्यतीत करता है। समझा जा सकता है कि जब बड़े इतना समय स्क्रीन को देते हैं तो अपने बच्चों को इसका इस्तेमाल करने से शायद ही रोक पाते होंगे। वैसे भी कोरोना काल में तत्कालीन विवशताओं की वजह से शिक्षा के लिए मोबाइल का प्रयोग अपरिहार्य हो गया था। जो मां-बाप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते थे उन्हें भी आगे बढ़कर अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल देना पड़ा था। और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि उनमें से बहुत सारे लोग उस मोबाइल को वापस लेना भूल गए हों।

हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि अधिकांश मां-बाप अपने बच्चों के प्रति अपने लाड का प्रदर्शन करने के लिए औचित्य की बहुत सारी सीमाओं की अनदेखी कर जाते हैं। वे बच्चों को बिना रोक-टोक के फास्ट फूड का उपभोग करने देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र बनने उससे पहले वे उन्हें अपने वाहनों की चाबियां सौंप देते हैं और लाड-लाड में न केवल उन्हें मोबाइल का निर्बाध प्रयोग करने देते हैं, खुद आगे बढ़कर उन्हें मोबाइल खरीद कर भी दे देते हैं। अगर मां-बाप न दें या देने की स्थिति में न हों तो बच्चे खुद लड-झगड़कर हासिल कर लेते हैं। बहुत बार यह भी देखा गया है कि ये सारी गतिविधियां करते हुए मां-बाप लज्जित नहीं गर्वित होते हैं।

इन बहुत सारी बातों के बीच से आज हम चर्चा यह करना चाह रहे हैं कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया का निर्बाध या सीमित उपयोग करने देना चाहिए? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि हाल में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने घोषणा की है कि सन 2025 की पहली दिसम्बर से वहां सोलह बरस से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इस निषेध का उल्लंघन करने पर यूट्यूब का 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर अर्थात लगभग 282 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। असल में वहां की सरकार ने एक अध्ययन करवाया जा जिससे ज्ञात हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में 10 से 12 बरस की आयु के 68 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ इस तरह का है कि वह बच्चों को खतरनाक स्टेट, हिंसा, डरावने दृश्यों और अश्लीलता भरे वीडियो या शॉर्ट्स बार-बार दिखाता है। इस कारण इन बच्चों में बहुत तेजी से डोपाइमाइन साइकल बनने लगा है और इसका कुप्रभाव उनकी नींद, पढ़ाई और मानसिकता पर पड़ रहा है। यहीं यह भी जान लें कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए टिकटोंक, इंस्टाग्राम, स्नैपैट और फ़ेसबुक का प्रयोग पहले से वर्जित है।

इसी ज्ञान में यह भी जान लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे देशों में बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर बंदिशें लागू हैं। फ्रांस में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वगैर माता-पिता की अनुमति के सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जैसे इतना ही पर्याप्त न हो वहां तो 15 वर्ष की उम्र तक के बच्चों द्वारा मोबाइल के उपभोग को पूरी तरह बंद करने के मामले में भी एक ट्रायल चल रही है। फ्रांस की ही तरह जर्मनी में भी 13 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे वगैर मां-बाप की अनुमति के सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बेल्जियम में यह प्रतिबंध 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रभावी है।

हमारे यहां अगर कानून बन भी जाएगा तो

यह निश्चित मानिए कि उसके पालन से

ज़्यादा उसका उल्लंघन होगा, और अंततः

वह कानून मज़ाक बन कर रह जाएगा।।

अधिकांश मां-बाप में इस समझ का अभाव

है कि मोबाइल और सोशल मीडिया का

अत्यधिक प्रयोग उनके बच्चों के मानसिक

स्वास्थ्य के लिए घातक है। उन्हें यह बात

समझाने का न तो किसी में धैर्य है, न

उत्साह और न इच्छा।

रोका गया था। यह बात अलग है कि वहां बाद में यह प्रतिबंध हटा लिया गया। संयुक्त राज्य अमरीका में चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवैसी प्रोटेक्शन एक्ट के अन्तर्गत 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निजी जानकारी एकत्रित करना वर्जित है। और यूरोपीय संघ, फ्रांस और स्पेन जैसे देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग के लिए मां-बाप की सहमति अनिवार्य करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

अब ज़रा एक नज़र अपने देश की स्थिति पर भी डाल लें। अप्रैल 2024 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद का विचारणीय विषय बताते हुए इस याचिका को खारिज़ कर दिया। असल में अभी भारत में बच्चों के सोशल मीडिया उपभोग को प्रतिबंधित करने पर कोई गंभीर विचार नहीं हो रहा है। इसकी बजाय हम सामाजिक सहमति, अभिभावकों के विवेक और डेटा सुरक्षा पर भरोसा कर रहे हैं।

सोशल मीडिया और स्क्रीन के प्रयोग, प्रयोग के सीमा उल्लंघन और प्रयोग के खतरों से हम सभी वाकिफ़ हैं। बच्चों के हाथ में जब स्क्रीन होता है तो वे उस पर किस तरह का कंटेंट देखते हैं, इस बात पर बड़ों का बहुत कम नियंत्रण संभव होता है। भारत जैसे देश में जहां मां-बाप अपनी रोज़ी-रोटी की समस्याओं में बहुत बुरी तरह उलझे होते हैं, उनसे यह उम्मीद करना कि वे यह देखेंगे कि बच्चे मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग किस काम के लिए कर रहे हैं, उनके प्रति ज़्यादती ही होगा। स्कूलों की हो हालत है,खास तौर पर सरकारीस्कूलों की, वहां काम के बोझ से दबे (और कभी-कभी काम से बचने वाले भी) अध्यापकों से कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। यह भी सही है कि आज मोबाइल हम सबके लिए इतना अपरिहार्य हो गया है कि उससे बच्चों को वंचित रखना व्यावहारिक नहीं रह गया है। मोबाइल तो उन्हें देना ही पड़ेगा। और जब आप उन्हें यह उपकरण सौंप देंगे तो फिर वे उसका कैसा उपयोग करेंगे, यह तय करना आपके लिए बहुत कठिन है।

और बात केवल बच्चों की नहीं है। यह भी देखा जाए कि बड़े भी मोबाइल के किस तरह एडिक्ट हो चुके हैं। इस बात की विस्तृत विवेचना अनावश्यक है। अब जो मां-बाप खुद मोबाइल से चिपके हुए हैं वे अपने बच्चों को इसका प्रयोग करने से कैसे रोकेंगे? बहुत बार तो हम देखते हैं कि मां-बाप इस बात पर गर्व करते हैं कि उनका शिशु मोबाइल के बगैर खाना तक नहीं खाता है या उनका बारह वर्ष का बेटा किस फरट्टे से स्कूटर दौड़ाता है। यह बताते हुए उनके चेहरे पर अपराध बोध नहीं गर्व झलकता है। बहुत सारे शिक्षक बताते हैं कि अगर वे बच्चों को फास्ट फूड का प्रयोग करने से रोकते हैं तो उनके मां बाप लड़ने के लिए आ जाते हैं।

ऐसे में भारत जैसे देश की स्थितियां अन्य देशों से बहुत अलग हैं। हमारे यहां अगर कानून बन भी जाएगा तो यह निश्चित मानिए कि उसके पालन से ज़्यादा उसका उल्लंघन होगा, और अंततः वह कानून मज़ाक बन कर रह जाएगा। अधिकांश मां-बाप में इस समझ का अभाव है कि मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग उनके बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। उन्हें यह बात समझाने का न तो किसी में धैर्य है, न उत्साह और न इच्छा। ऐसे में जो समझदार लोग हैं वे दुखी होते रहेंगे, और उनके बच्चे यह देखकर अपने मां-बाप पर कुढ़ते रहेंगे कि उनके अन्य दोस्तों के मां-बाप जिस काम के लिए अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रोक रहे हैं, उसी काम के लिए उनके मां-बाप उनसे रोज़ किंच-किंच क्यों करते हैं। ऐसे में बस यही संभावना बची रहती है कि जो मां-बाप इस बात को समझते हैं वे अपने बच्चों के सोशल मीडिया और स्क्रीन प्रयोग पर निगाह रखें और प्रयास करें कि बच्चे इनका सीमित प्रयोग करें।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)



बालमुकुंद आन्ना

राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बीते 2022 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। छात्रों के साथ ही छात्र संगठन लगातार चुनाव की मांग करते आ रहे हैं। गहलोत सरकार ने 2023 में विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव स्थगित किये थे। इसके बाद आई भाजपा सरकार ने भी चुनाव कराने की कोई घोषणा नहीं की है। दिल्ली विश्व विद्यालय छात्र संघ के चुनावों के बाद राजस्थान में भी छात्र संघों के चुनावों की मांग जोर शोर से उठ रही है। राजस्थान में छात्रसंघ चुनावों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं छात्र संघों के चुनाव कराने को लेकर छात्र नेताओं

ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। छात्रों ने सरकार द्वारा छात्र संघों के चुनाव नहीं कराने के फैसले के विरोध में उठा आंदोलन शुरू किया है। इसको लेकर छात्र संघों व छात्र नेताओं का गुस्सा लगातार उबाल मार रहा है। छात्र राजनीति पूरी तरह ठप पड़ी है। छात्र नेताओं का कहना है लोकतंत्र का पहला दरवाजा छात्र संघ होता है। छात्र संघ से युवा निष्पक्ष चुनाव, मतदान व प्रचार का ककहरा सीखते हैं। निर्वाचित छात्रसंघ न होने से छात्रों की समस्याएं अनसुनी रह जा रही हैं और प्रतिनिधित्व का अभाव गहरी निराशा पैदा कर रहा है। छात्र संगठनों व छात्र नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार जान-बूझ कर चुनाव की प्रक्रिया को टालता आ रहा है। राजस्थान विश्व विद्यालय छात्र संघ देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।

यहां के छात्र नेता सिर्फ युनिवर्सिटी अथवा कॉलेज तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आगे चलकर देश और प्रदेश की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। जो इस सीढ़ी को चढ़ गया वह राजनीति के ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है। छात्र संघ के कई नेता बाद में राजनीति के दिग्गज चेहरे भी बने हैं। प्रदेश में कई साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज भी प्रदेश की सियासत में छात्र राजनीति से निकले

नेताओं का बोल बाला है। छात्र संघ चुनाव में राजनीति का पहला ककहरा सीखा जाता है। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक तक हर स्तर पर प्रभावशाली नेता दिए हैं। छात्र संघ की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं, जो न केवल छात्रों की समस्याओं के समाधान का मंच रहा है, बल्कि प्रदेश की सियासत को भी दिशा देने वाला स्तंभ साबित हुआ है। समय की माँग है कि छात्र संघ को फिर से जीवित किया जाए।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनावों के मधे नज़र राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में होने वाले छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। गहलोत ने ही अपने कार्यकाल में चुनावों पर रोक लगाई थी जो भाजपा सरकार के दौरान भी बंदसतूर जारी है। राज्य की राजनीति में आज भी कई ऐसे नेता उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपना सियासी सफर शुरू किया है। आज देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी युवा है। जो अपने माताधिकार का उपयोग कर देश तथा प्रदेश की सरकार बनाती है। इतनी बड़ी आबादी का वोट सरकारें तय करती हैं। दूसरी तरफ छात्र संघों के चुनाव प्रदेशभर में प्रतिबंधित है। यह विचारणीय है।

एक छात्र नेता ने युनिवर्सिटी की राजनीति से निकले राजस्थान के प्रसिद्ध नेताओं के कटआउट लगाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया और छात्र संघ चुनाव की मांग की। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगाए कटआउट के जरिये बताया गया कि अनेक नेता और मंत्री छात्र संघों के जरिये सियासत में अपनी मजबूत स्थिति संभाले हुए हैं। छात्र संघ चुनाव की बंदौलत ही आज देश और प्रदेश को ऐसे संघर्षशील नेता मिलें है जो हर परिस्थिति में पीड़ितों ओर शोषितों की आवाज मजबूती से उठाते हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्रसंघ चुनावों पर रोक की पहली सीढ़ी है और इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। प्रदर्शन में छात्र राजनीति से निकल मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बनने वाले अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी, कालीचरण सराफ, हनुमान बेनीवाल, रघु शर्मा, सतीश पुनिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, विकास चौधरी, महेंद्र चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी, मनीष यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, अशोक लाहोटी, हरीश चौधरी, राजपाल सिंह शेखावत, रामलाल शर्मा,मुकेश भाकर, रामनिवास गवाड़िया, अभिमन्यु पुनिया और राजकुमार शर्मा के कट-आउट लगाये थे। सरकार ने लिंगदोह समिति की

शर्तों की पालना नहीं होना भी चुनाव नहीं कराने का एक कारण बताया है। देखा जाता है छात्र संघ चुनावों में लिंगदोह समिति की अचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। चुनाव एक मखौल बनकर रह जाता है। जाति और धनबल का खुला प्रदर्शन देखने को मिलता है। हिंसात्मक घटनाएं आम हो गई हैं। लिंगदोह समिति ने देश के विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्रसंघ चुनावों के लिए कुछ सिफारिशें जारी की थीं, जिनका उद्देश्य बाहुबल और धनबल के प्रभाव को रोकना और चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाना था। सिफारिशों के अनुसार, कोई छात्र केवल एक बार चुनाव लड़ सकेगा, और चुनाव में अधिकतम 5,000 रुपये खर्च किए जा सकेंगे। उम्मीदवार और उनके संगठन पर चुनावी चंदा लेने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, विज्ञापन और बैनर पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। कॉलेज परिसर में किसी प्रकार के हथियार लाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार पर दो साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा, और उस साल की परीक्षा में भी वह वंचित हो जाएगा। वास्तविकता में लिंगदोह समिति की सिफारिशें कागजों में दबकर रह गई हैं।

–बाल मुकुन्द आन्ना,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड का सफर – राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षा की ओर बढ़ते कदम



डॉ. अमृता कटार्रा

जयपुर। राजस्थान के राजकीय विद्यालय अब परंपरागत शिक्षण विधियों से आगे बढ़कर डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। ब्लैकबोर्ड और किताबों की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए अब कक्षाएं स्मार्ट स्क्रीन, प्रोजेक्टर और डिजिटल कंटेंट से सजी हैं। राज्य सरकार की सूचना एवं संचार तकनीक योजना के तहत वर्ष 2024 तक 13,976 सरकारी विद्यालयों में

आईसीटी लैब्स की स्थापना की जा चुकी है। इनमें से 13,411 लैब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत हैं जबकि 565 आदर्श विद्यालयों की भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। प्रदेश के 13 हजार से अधिक विद्यालयों में 17,421 स्मार्ट क्लासों की स्थापना भी की गयी है।

इन लैब्स के माध्यम से विद्यार्थी अब बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के साथ ई-मेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आदि सॉफ्टवेयर पर कार्य करना, इंटरनेट सर्फिंग, विषय आधारित वीडियो लेक्चर देखना और इंटरएक्टिव डिजिटल कंटेंट से परिचय भी सीख रहे हैं। इससे खासतौर पर ग्रामीण व दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थी तकनीकी साक्षरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं और राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर की शिक्षा से जुड़ने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं।

शिक्षक- विद्यार्थी दोनों हो रहे डिजिटल रूप से दक्ष-ये प्रयोगशालाएं केवल उपकरणों का जमावड़ा भर नहीं हैं बल्कि यह एक

सशक्त डिजिटल कक्षा के रूप में विकसित की गई हैं, जहां विद्यार्थियों में तकनीकी दक्षता के साथ-साथ आत्मविश्वास, संवाद कौशल और निर्णय लेने की क्षमता जैसे जीवनोपयोगी गुणों का भी विकास हो रहा है। प्रत्येक लैब में कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, आवश्यक शैक्षिक सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है। साथ ही फर्नीचर, पावर बैकअप और सुरक्षा के मानकों का भी ध्यान रखा गया है ताकि तकनीकी शिक्षण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय में एक प्रशिक्षित आईसीटी प्रभारी शिक्षक की नियुक्ति की गई है जो न केवल लैब का संचालन करते हैं बल्कि विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षण में मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। यह शिक्षक समय-समय पर विद्यालय के अन्य स्टाफ व प्रशासन को भी डिजिटल उपकरणों के प्रभावी उपयोग हेतु प्रशिक्षित कर रहे हैं जिससे विद्यालय समग्र रूप से डिजिटल

रूपांतरण की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

तकनीक बनी सीखने का माध्यम- आज के विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं हैं। वे इंटरनेट के माध्यम से विषयवस्तु की खोज करने, डिजिटल नोट्स तैयार करने, वस्तुअलग विज्ञान में भाग लेने और ऑनलाइन कक्षाओं का हिस्सा बनने में पूरी तरह सक्षम हो रहे हैं। आईसीटी लैब्स एवं स्मार्ट क्लास ने विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया है। अब विद्यार्थी कंप्यूटर को केवल गेमिंग या मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि अपने भविष्य निर्माण का एक शक्तिशाली औज़ार समझने लगे हैं। राज्य के शिक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों पर ई-क्लास वीडियो, एनिमेटेड प्रजेन्टेशन और पावरपॉइंट लेक्चर जैसे डिजिटल कंटेंट समय-समय पर तैयार किए जा रहे हैं। ये सामग्री आईसीटी लैब्स के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है। इससे न केवल विद्यार्थियों की

समझ में सुधार हुआ है बल्कि विज्ञुअल लर्निंग के कारण उनकी याददास्त और विषय पर पकड़ भी पहले से बेहतर हो रही है। यह दृष्टिकोण परंपरागत शिक्षा प्रणाली से हटकर एक सहभागी और बहुआयामी शिक्षण वातावरण की ओर बढ़ता कदम है।

मॉडल राज्य के रूप में स्थापित होगा राजस्थान -शिक्षा विभाग के प्रयास और सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से राज्य के राजकीय विद्यालय अब डिजिटल इंडिया की रफ्तार से कदमताल कर रहे हैं। आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लास न केवल विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सशक्त बना रही हैं बल्कि उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रही हैं। यह पहल राजस्थान को न केवल डिजिटल शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेगी।

–डॉ. अमृता कटार्रा,
सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

मीरा महोत्सव में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मीरा बाई के दर्शन किये

मेड़ता सिटी, (निसं)। विश्व ऐतिहासिक चारभुजानाथ के 521वें मीरा जयंती महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शिरकत की।

महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने चारभुजानाथ व रजत रेवाड़ी के दर्शन कर महिलाओं के साथ भजनों का लाभ उठाया व महोत्सव में मीरा स्मारक के कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं महिला बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरू, खीवसर विधायक रवेतराम डांग, जनता प्रभान संदीप चौधरी, मेड़ता नगरपालिका अध्यक्ष शोभा लाहोटी, किन्नर समाज गादीपति राजकुमारी बाई कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर मीरा जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष व पूरी टीम के द्वारा उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। मीरा महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मीरा बाई के दर्शन किये।

इस मौके पर दीया कुमारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मेड़ता मीरा की नगरी है, यहां आने का मौका इस



मीरा महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने महिलाओं के साथ भजनों का आनंद लिया।

महोत्सव में ही मिलता है। दीया कुमारी ने कहा कि मेड़ता में जो भी विकास कार्य होंगे वो गुणवत्ता के साथ होंगे। मेड़ता में एक पैरोनामा जल्द ही बनने जा रहा है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। भारत सरकार व राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए

भी कार्य कर रहे हैं। वहीं जहां पर कोई भगवान या भक्त सहित कई लोगों के सन्किल उनके नाम से निर्माण कराने का प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों द्वारा आयेगा उस पर कार्य किए जाएंगे। महिला बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार ने कहा मेड़ता भक्ति भाव की

नगरी है। यहां के नागरिक प्रेम भाव से भरे हुये हैं। मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरू ने कहा कि उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा मीरा महोत्सव को सरकारी कैलेंडर में स्थान दिलाने पर पूरा मेड़ता इनका आभारी है। मेड़ता से इनका सम्बन्ध पुराना है।

- ‘मेड़ता में एक पैरोनामा जल्द ही बनने जा रहा है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है’
- दीया कुमारी ने चारभुजानाथ व रजत रेवाड़ी के दर्शन कर महिलाओं के साथ भजनों का लाभ उठाया

इसलिए मेड़ता क्षेत्र में विकास की गंगा बही है और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाया है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी पूनम चोयल, जितेंद्र गहलोत मीरा महोत्सव समिति अध्यक्ष, सचिव विप्रकाश कमेडिया, विरमदेव सिंह जैसास, अभय सिंह भेसड़ा, ऋषभ राठी, लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा, उमा शर्मा रंजत, वदरथ सारस्वत, कैलाश गौड़, मोहित माली, रवि गहलोत सहित कई लोग मौजूद थे।



पंडित अनिल शर्मा

मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज सर्वोच्च सिंधि योग सूर्योदय से प्रातः 9:13 तक है। रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। धनरा रात्रि 12:47 से आरम्भ होगी। आज चतुर्थ सावन वन सोमवार व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:36 तक, शुभ 9:15 से 10:54 तक, चर 2:12 से 3:51 तक, लाभ-अमृत 3:51 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:56, सूर्यास्त 7:09

राशिफल

सोमवार 4 अगस्त, 2025

सावन मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत् 2082, अनुराधा नक्षत्र प्रातः 9:13 तक, ब्रह्म योग प्रातः 7:05 तक, गर करण दिन 11:42 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संसार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरु-

मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज सर्वोच्च सिंधि योग सूर्योदय से प्रातः 9:13 तक है। रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। धनरा रात्रि 12:47 से आरम्भ होगी। आज चतुर्थ सावन वन सोमवार व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:36 तक, शुभ 9:15 से 10:54 तक, चर 2:12 से 3:51 तक, लाभ-अमृत 3:51 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:56, सूर्यास्त 7:09



मेघ

पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य परेशानी हो सकती है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।



तुला

आर्थिक कारणों से अटक हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।



वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मिथुन

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।



धनु

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



कर्क

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।



मकर

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन में वृद्धि होगी। अटका हुआ अथन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित प्रेरणा मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में आपसी अनबन-मतभेद हो सकते हैं। अतिथियों से आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।



कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है।



मीन

नवीन कार्यों के

**‘घर का पूत कुंवारा डोले, पाड़ोसी का फेरा’
एसएमएस हॉकी ग्राउंड में लगा असुविधाओं का
अंबार, खेल विभाग द्वारा अनदेखी का आरोप**



जयपुर, ३ अगस्त। एक मारवाड़ी कहावत बहुत प्रचलित है कि " घर का पुत कुंवारा डोले, पाड़ोसी का फेरा"। यह कहावत खेल विभागे के उस फैसले पर खरी उतरती है कि आरसीए अकादमी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद भवन रखा जा रहा है जोकि राजस्थान क्रिकेट ऑर हॉकी जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जबकि दूसरी ओर सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थित हॉकी ग्राउंड का हाल बंद से बदतर हो रहा है। उस ओर खेल विभागे का ध्यान बिचकुल भी नहीं जा रहा है।

अगर खेल विभागे चाहता तो जब से हॉकी ग्राउंड पर एस्ट्रोफ़ लगा है तब से आज तक हॉकी ग्राउंड का नाम हॉकी लेजेंड ध्यानचंद हॉकी ग्राउंड रखा जा सकता था, इसके साथ ही खेल विभागे की ओर से मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि होती। मगर "बाद री हॉकी तेरी किस्मत" हॉकी ग्राउंड की अनदेखी कर क्रिकेट अकादमी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद भवन रखा जा

रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ एक करोड़ रुपये की राशि सवाई मान सिंह स्टेडियम स्थित हाँकी मैदान में हाँकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा (स्टैच्यू) व भवन निर्माण हेतु तत्पर है व कमेटी का मानना है कि हाँकी भवन व मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का निर्माण मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, साथ ही राज्य हाँकी के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा भी देगा।

होना तो यह चाहिए कि खेल विभाग खिलाड़ियों को हॉकी के विभिन्न पहलुओं, जैसे शारीरिक, मानसिक और सामरिक, में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करें और छात्रों को समय प्रबंधन, स्वतंत्रता और संगठनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करें लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में एक अंतरराष्ट्रीय टर्फ हॉकी स्टेडियम है। यह स्टेडियम एक अन्य खेल विविधियों के साथ-साथ हॉकी के लिए भी एक प्रमुख स्थान है। यहां विश्व स्तरीय

अंतरराष्ट्रीय हॉकी ग्राउंड है।

जयपुर में आज से दो दशक पहले एस्ट्रोडफ हॉकी ग्राउंड पर लगाया गया था ताकि राजस्थान के हॉकी ग्राउंड पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेला जा सके और राजस्थान के खिलाड़ियों का एस्ट्रोडफ में खेलने की प्रैक्टिस हो सके साथ ही अपने खेल प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल सके। इसका किना फायदा खिलाड़ियों को मिला है ये सभी जानते हैं। फिर दुबारा इसका रनोवेशन ऑफ सिनैथेटिक हॉकी एस्ट्रोडफ मैदान का लोकार्पण रविवार, दिनांक 29.5.2022 को किया गया जिसका लोकार्पण का पत्थर लगा हुआ है। हॉकी ग्राउंड के गेट के पास। कुल मिलाकर खेल निषाण को हॉकी ग्राउंड और हॉकी खिलाड़ियों की सुविधाओं की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है अन्यथा हॉकी ग्राउंड एवं हॉकी खिलाड़ियों का भविष्य संवर नहीं सकता है।

राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को विश्व स्तर पर पहुंचाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा

हाँकी ग्राउंड में आने वाले खिलाड़ियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेलमंत्री राज्यधर सिंह ठाकुर खेल और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना चाहते हैं वहीं खेल विभाग हाँकी ग्राउंड पर आने वाले खिलाड़ियों की जान का इशम बना हुआ है। ग्राउंड में खिलाड़ियों के लिए लोए टूट टीन शरके के अंदर बिजली के तार और बोर्ड जमीन पर टूट पड़े हुए हैं जिससे किसी भी खिलाड़ी को करंट लग सकता है। खिलाड़ियों की जान की कोई सिक्क्योरिटी नहीं है। अगर खिलाड़ियों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? इसका कोई जवाबदेही नहीं है। खिलाड़ियों के बैटन की कुर्शियाँ भी गायब हैं। हाँकी ग्राउंड पर खूब एडवेंचर में कचरे की जगह बरसात का पानी बरा हुआ है और लोहे की जालियाँ के पास कचरे का अंबार लगा हुआ है। ताज्जुब कि बात तो यह है कि कीमती पुराने एस्ट्रोडर्फ को काटकर कचरे को ढकने के काम में लिया जा रहा है। एस्ट्रोडर्फ इस हाँकी ग्राउंड के लिए पुराना हो गया होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस एस्ट्रोडर्फ को खुले आसमान के नीचे सड़ें, गर्मी और बरसात की भार झेलने के लिए खुले में पकड़ दिया जाए जोहादी की जालियों को भी खुले में रखा गया है जिसमें आधे से ज्यादा लोहे को जंग लग गई है। पुराने गोल पोस्टों की भी हालत भी ऐसी ही है। इस लगता है कि नए नए खेल सामान ग्राउंड पर लगाए जाए और पुराने फेंक दिए जाए। ये सभी पुराने सामान और जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन कौन जिम्मेदार नहीं है। हाँकी ग्राउंड के बाहर कचरे का ढेर लगा हुआ है। उस और किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, और कोच का ध्यान ही नहीं जाता है।

राजस्थान शतरंज संघ में विवाद
19 वर्षों से खिलाड़ियों को टीए/डीए नहीं

जयपुर, 3 अगस्त। राजस्थान शतरंज संघ में लंबे समय से चल रहा प्रशासनिक विवाद अब गहराता जा रहा है। संघ के अध्यक्ष और उनके समर्थक कुछ जिला पदाधिकारी ने सिविल राज्य संघ संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बल्कि रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा दिए गए स्पष्ट आदेशों की अवहेलना कर हुए अवैध चुनाव की घोषणा भी कर चुके हैं।

इस पूरी स्थिति का सबसे दुखद पहलू यह है कि फिलिप 19 वर्षों से राज्य के शतरंज खिलाड़ियों को टीए/डीए तक नहीं मिल रहा है। आसपीए बीते 15 वर्षों से "डिफरन्ट (अकार्यपट) स्थिति" में है। इतना ही नहीं, वक्तो 2005 से लेकर 2021 तक आसपीए को न तो कोई वेतन चुवाना कराए गए और न ही किसी प्रकार को ऑर्डर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इन्हीं आधारों पर राजस्थान राज्य खेल परिषद ने आसपीए को विवादित खेलों की सूची में डाल रखा है, और अब तक उसे मान्यता नहीं दी है।

आरसीए का वर्तमान विवाद कैसा शुरू हुआ?
यह विवाद उस समय सामने आया जब जयपुर जिला शतरंज संघ ने जयपुर में फरवरी 2024 में नेशनल एमेच्योर प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसी दौरान कुछ खिलाड़ियों-जिन्होंने अपने खिलाड़ी कार्डों में 'आरसीए' लिखा था-पर पहले से ही जिला रजिस्ट्रार और खेल आयोग के खिलाफ विवाद चल रहा था। जिला कार्यालयों में जांच लंबित थी-ने मिलकर आरसीए के सचिव को निलंबित करने का फैसला किया।

साजिश रची। यह निलंबन पत्र अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया, जबकि आरसीए के संविधान के अनुसार अध्यक्ष को ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक आरोप लंबित है।

इसके बावजूद पूर्व अध्यक्ष के गुट ने अवैध चुनाव की घोषणा कर दी है, और जिला सचों पर इस गैरकानूनी प्रक्रिया में भाग लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अध्यक्ष द्वारा अखिल भारतीय शतरंज संघ में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, आरसीए सचिव द्वारा भेजे गए राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को भी रोकता गया है।

खिलाड़ियों की मांग और भावध्व
राज्यभर के खिलाड़ी और कोच इस स्थिति से अवगत हो पेशान हैं। टीए/डीए की अनुपलब्धता, टूर्नामेंटों की अनिश्चितता, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी ने खेल प्रतिस्पर्धियों को भविष्यतः क्या है, खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक आरसीसी में वैध एडवांस्ड समिति नहीं बनती या सरकार भावध्व हस्तक्षेप नहीं करती, जब तक उनका भावध्व अधर में ही रहेगा। वे राज्य सरकार से यह अपील कर रहे हैं कि आरसीसी में तत्काल स्वतंत्र, निष्पक्ष और वैध चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि संघ को दोबारा कार्यरत बनाकर खिलाड़ियों को उनका उचित लाभ दिलाना जा सके।

आयु धोखाधड़ी रोकने के लिए करने जा रहा है स्क्रीनिंग एजेंसी नियुक्त : बीसीसीआई

मुम्बई, 3 अगस्त। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) आयुध धोखाधड़ी रोकने और खिलाड़ियों को योग्यताओं के स्थापन के लिए एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त करने जा रहा है। बीसीसीआई के अनुसार आयुध-धोखाधड़ी रोकने और खिलाड़ियों को योग्यताओं के स्थापन के लिए एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त की प्रक्रिया में है। हाल ही में एयरएफपी जारी किया गया है, जिसमें स्थापित संस्थाओं से बोलियों आमंत्रित किया गई है। इस आउटसोर्स एजेंसी के अप

के अंत तक स्थापित होने की उम्मीद है।
ऐसा माना जा रहा है कि यह मामला
खिलाड़ियों द्वारा प्रत्यक्ष किए गए दस्तावेजों
या प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए संबंधित
बीसीसीआई का उद्देश्य इस प्रक्रिया
पेशेवर बनाना और अधिक आयु
खिलाड़ियों के इस प्रणाली में प्रवेश करने
की किसी भी संभावना को समाप्त करना
है। बीसीसीआई दो-स्तरीय आयु
सत्यापन प्रणाली अपनाता है - पहले
दस्तावेजों और जन्म प्रमाण पत्रों की जाँच
शाली है, जबकि दूसरा अस्थि परीक्षा
है, जिसे अमत 3 पर टीडब्ल्यू (टेनर
व्हाइटास 3) पद्धति के रूप में जाना

जाता है। ये सत्यापन आमतौर पर लड़कों के लिए अंडर-16 स्तर पर और लड़कियों के लिए अंडर-15 स्तर पर किए जाते हैं।

बीसीसीआई ने बोली लगाने वाली संस्थाओं से अपेक्षित आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार की है। एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, बोली लगाने वाली कंपनियाँ/एजेंसियों के पास प्रतिष्ठित फर्मों की छठमिनी सत्यापन सेवाएँ प्रदान करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इनमें कॉर्पोरेट कंपनियाँ और गैर-बोर्ड/संस्थाओं और भर्ती निकाय शामिल हैं।

लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

इसके अलावा, इच्छुक पक्षों के पास एक राष्‍ट्रप्यापी नेटवर्क या सभी भारतीय राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भौतिक और डिजिटल दोनों तरह से सत्यापन करने की क्षमता होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई वगैरें में इसी समय जुलाई और अगस्‍त के आसपास आप सत्यापन करवा सकते हैं। इस वष र यह प्रक्रिया सितंबर तक भी बढू वजती है क्योंकि एजेंसी के इस मर्जे के अंत त काम शुरु करती की उम्मीद है। सत्यापन राष्‍ट्रवार किया जाता है और प्रत्येक राज्‍य से, प्रत्येक बालक और बालिका का वय, 40-50 डिजिटलडिजि में की पक्षधन प्रक्रिया से गजरना पडता है।

ओवल टेस्ट-खराब लाइट से चौथे दिन का खेल जल्दी खत्म
ब्रूक-रूट के शतक, इंग्लैंड जीत से 35 रन दूर

लंदन, 3 अगस्त। हैरी ब्रूक (111) और जो रूट (105) की शानदार शतकीय पारियों के बाद बारिश के खलल के कारण दिन का खेल समाप्त किये जाने के समय इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट के चौथे दिन रविवार को दूसरी बार जीत के साथ 339 रन बना लिए हैं और वह जीत से अब 35 रन दूर है।

चायकाल के बाद चार विकेट पर 317 रनों से ओपेनरलैंड ने खेलना शुरू किया। इसी दौरान जो हट्ट ने अपना शतक पूरा किया। हट्ट ने 152 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 105 रनों की पारी खेली। उन्हें प्रसिद्ध कृष्ण ने विकेट परी छेड़ बुरेल के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्ण ने जेबेकन फेयर (पांच) को बोल्ड कर मैच को एक बार पल्लभ भारत की ओर मोड़ दिया। 77वें ओवर में खराब गेंदानी के कारण खेल रोक दिया। उसके बाद बारिश होने लगी। मैदानी अमपर्ययों ने मैदान का निरीक्षण करने के बाद दिन का खेल समाप्त किया जाने की घोषणा की। इंग्लैंड ने टेस्ट के समय छह विकेट पर 339 रन बना



लिये हैं और जेमी स्मिथ नाबाद (दो) और जेमी ओवर्टन बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड को जहां जीत के लिए 35 रनों की जरूरत है वहीं भारत को चार विकेट की दरकार है। भारत की ओर प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन और मोहम्मद सिराज ने दो विकेट लिये। आकाश दीप ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले ब्रूक ने 98 गेंदों पर 111 रन की तेज-तर्रार पारी में 12 चौके और दो

छक्के लगाए। आकाशदीप ने चायकाल से पहले ब्रूक को आउट किया लेकिन तब तक वह इंग्लैंड को जीत की राह पर अग्रसर कर चुके थे। इस सेशन में कुल 153 रन बने और सिर्फ एक विकेट गिरा है। इसी से पता चलता है कि यह मैच अब किस स्थिति में है। हल्की बून्दा-बांदी हो रही है। अगर यह जारी रहा तो भारत के तेज गेंदबाजों को आराम करने का और कुछ मैजिक करने के लिए रिफ्रेश होने

एचसीएल इंडिया स्वचैश दूर का पहला चरण आज से मिस्र के यासिन शोहदी और नूर खफागी को मिली शीर्ष वरीयता



**अश्विनी विश्नोई ने
बढ़ाया राजस्थान
का मान : सीएम**

जयपुर, 3 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर विश्व कुरती चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता भोलवाड़ा निवासी अश्विनी विश्नोई ने मुलाकात की। शर्मा ने दुपट्टा ओढ़ाकर उनकी को सम्मान किया तथा उनको इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को तलाशने और ताराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। भोलवाड़ा की बेटी अश्विनी ने कुरती में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे विश्व में राजस्थान का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने अश्विनी विश्नोई को इस सफलता में मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके पिता मुकेश विश्नोई को भी बधाई दी। उल्लेखनीय है कि अश्विनी विश्नोई ने एथेंस में अंडर 17 वर्ल्ड कुरती चैम्पियनशिप के 65 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ ही अश्विनी वर्ल्ड कुरती चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रदेश की प्रथम महिला पहलवान बनी है।

जयपुर, 3 अगस्त। स्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया और एचसीएल के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार से यहां शुरु हो रहे एचसीएल इंडिया स्वैश दूर 2025 के पहले चरण में मिश्र के यासिन शोहदी और नूर खफागी को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता दी गई है। भारत की स्टार स्वैश खेल्यर जोशना चिन्पाना और निरफया दुबि के दूर्यार्मन की शुरुआत से टीक एक दिन पहले अपना नाम वापस लेने से राजस्थान की छवि सारण को मेन ड्रॉ में जगह मिल गई। स्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की उपाध्यक्ष सुरभि मिश्रा ने रविवार को यहां बताया कि सोमवार से शुरु हो रहे मुकाबलों में मिश्र के यासिन शोहदी को शीर्ष वरीयता दी गई है। वहीं जापान के

ठोमा एंडो को दूसरी, श्रीलंका के रविन्दु
 लेक्सिस को तीसरी और मलेशिया के
 विलेस प्रग्रास को चौथी वरीयता मिली है।
 उन्होंने बताया कि पुरुष वर्ग में टॉप-8 में
 सूज कुमारा चन्द एकमात्र भारतीय हैं,
 जिन्होंने छठी वरीयता दी गई है। भारत के
 राहुल बैथा, आर्यवीरो दीवान, अयान जवीर
 अली और दिवाकर सिंह भी चुनौती पेश
 करेंगे। सुप्रिथ ने बताया कि महिला वर्ग में
 भी मिश्र की नूर खफागी टॉप सीड है। वहीं
 मिश्र की ही मेना वलदीव को दूसरी, जापान
 की अकारा मिडोरिकावा को तीसरी और
 मलेशिया की गो झी शुआन को चौथी
 वरीयता है। उन्होंने बताया कि टॉप-8 में
 शामिल चार भारतीय खिलाड़ियों तन्वी
 खन्ना को पांचवीं, अंजली सेमवाल को
 छठी, शमीना रियाज को सातवीं और
 जेनिट विंधि को 8वीं वरीयता दी गई है।
 महिला वर्ग के मेन ड्रा में भारत की कुल
 17 खिलाड़ी हैं, जिनमें सान्वी बतर, पूजा
 अतीर, अराधना कस्तुरी राज, अनिका दुबे
 तानिका जैन, आसफ़ा पोडवाल, नयना
 बरस और उन्नित पिपाटी आदि शामिल हैं।

सुरभि मिश्रा ने कहा कि 2028 में होने वाले लास एंजेलिस ओलंपिक में स्वर्णश्री को भी शामिल किया गया है। इसे देखते हुए ही फेडरेशन और एचसीएल इंडिया ने इंडिया स्वर्णश्री दूर की शुरुआत की है। जयपुर के बाद इंडिया दूर के आगामी चरण मुम्बई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और दिल्ली में खेले जाएंगे। इससे भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय कॉम्पिटिशन में मदद आएगी और राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में मदद मिलेगी।

ज्यादा खेलना बोरियत और ठहराव का कारण बनेगा, आईसीसी को ध्यान देने की जरूरत : गृध

लंदन, 3 अगस्ता। भारत और इंग्लैंड के बीच वर्तमान में पांच मैच की ओ टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। जिससे लेकर फैसलें कराए जा रहे हैं। हालांकि, महान बल्लेबाज ग्राहम गूच ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर आईसीसी को सभ्यता से नकार दिया है। वहीं ग्राहम गूच का कहना है कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही पांच मैच की कड़ी सीरीज दबाव श्रेल रहे। टेस्ट फॉर्मेट के लिए बिकुल सही प्रेरणा है लेकिन उन्हें डाई शी है कि सिर्फ बिग थ्री (भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया) के एक-दूसरे के साथ ज्यादा खेलने का मौजूदा चलन ही अंततः बोरीयन और ठरवाय का कारण बनेगा। अधिकतर टेस्ट क्रिकेट भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। टेस्ट जो पांच की सीरीज में एक-दूसरे के साथ खेलते हैं। वेस्टइंडीज, साउथअफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे आर्थिक रूप से कमजोर देश केवल दो या तीन मैच की सीरीज ही खेलते हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान गूच ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को बिग थ्री देशों से आगे बढ़कर फलाने-फूलाने की जरूरत है। गूच ने और कहा कि, मुझे लगता है कि आईसीसी का टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देने की जरूरत है और वे देखने की जरूरत है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर देशों की कैसे मदद कर सकते हैं।

डब्ल्यूसीएल का भारत को समर्थन देना पीसीबी को नागवार गुजरा

नई दिल्ली, 3 अगस्त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूएलएस) को आयोजकों पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए इसे पहलवान आतंकवादियों हलके के बाद पाकिस्तान के साथ भारतीयों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। भारतीयों ने पहलेगांधी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। भारतीयों ने पहलेगांधी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। भारतीयों ने पहलेगांधी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

मुक़ाबले और सेमिफाइनल ड्रॉस में खेलने से इनकार कर दिया गया जिसके बाद पीसीबी ने यह फैसला किया।



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN



RISING RAJASTHAN
PARTNERSHIP
CONCLAVE
11 & 12 MAY 2025
— IDEAS & IMPACT —

प्रत्यक्ष आवंटन योजना - 2025

राजिग्न राजस्थान में MoU करने वाले निवेशकों के लिए भूखण्ड के आरक्षित मूल्य पर

औद्योगिक भूखण्डों का डायरेक्ट अलॉटमेंट

चतुर्थ चरण

आवेदन एवं EMD की अंतिम तिथि

07 अगस्त, 2025 (सायं 6 बजे तक)

विभिन्न श्रेणियों / वर्गों के लिए आरक्षित भूखण्ड

ई-लॉटरी

12 अगस्त, 2025

218 महिला वर्ग

248 अनुसूचित जाति/अनुसूचित

101 औद्योगिक क्षेत्र

6,313 अनादरित भूखण्ड

154 भुगर्भ जल

7,123 कुल औद्योगिक भूखण्ड

42 खियाजित लागाटिडरक भूखण्ड

126 रेलगाडी डिवायन

64 कपड़ों के कारखानों के लिए भूखण्ड

अंतिम

4

दिन शेष

आवंटन की प्रक्रिया

एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन

EMD - भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाइन जमा।

पात्रता - निवेशक जिन्होंने 09/07/2025 तक राजिग्न राजस्थान में राज्य सरकार के साथ एमओयू किये हैं वे सभी इस स्कीम में भूखण्ड के लिए पात्र हैं।

भूखण्ड की राशि का भुगतान

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान या

RIICO की टर्म लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण

5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ

औद्योगिक क्षेत्रों में नियोजित लॉजिस्टिक भूखण्डों के आवंटन से संबंधित पॉलिसी riico.raajasthan.gov.in पर देखें।

इस योजना के तहत भूखण्ड देखने या आवेदन करने के लिए <https://riico.raajasthan.gov.in> पर दिए गए Direct Land Allotment लिंक पर क्लिक करें अथवा SSO Portal पर login के बाद RIICO के आइकन पर क्लिक करके Land Allotment पर जाएं और Direct Land Allotment Policy - 2025 (for RR MoU Holders) पर क्लिक करें।

*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

हैल्पलाइन नंबर : 0141 4593250, 4593237 | वॉट्सएप : +91 98013 06515 | ई-मेल : riico@riico.co.in
riico.raajasthan.gov.in - ricogis.raajasthan.gov.in / ricogiscitizen

राज.संसाधन / सी / 25 / 7387



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत बिल्व का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने चाहिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जोधपुर हाउस में बिल्व का पौधा लगाया

दिल्ली में पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने रिफाइनरी के काम में तेजी लाने की बात कही

नई दिल्ली/जयपुर, 3 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत बिल्व का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिल्व जैसे पौधे धार्मिक और औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने चाहिए।

शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के

- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन तथा विरासत से जुड़े पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जायेगा। प्राचीन हवेलियों और हेरिटेज सम्पत्तियों की सूची बनवाई गई है तथा उनके उचित रखरखाव के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी।

बीकानेर हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि हमारी सरकार राजस्थान के चर्हुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। राजस्थान रिफाइनरी

के काम में तीव्रता लाकर यहां बनने वाले बाय-प्रोडक्ट्स को संसाधित करके इससे जुड़े उद्योगों की स्थापना पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम

किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से धार्मिक अब पेरलीक का मामला जयपुर ट्रांसफर होने के बाद जब्त कैश और अन्य माल ईडी कोर्ट को भेज दिया गया।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर सेना के अधिकारी व एयरलाइन कर्मचारियों में मारपीट

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई

श्रीनगर, 3 अगस्त। श्रीनगर में हवाई अड्डे पर सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक निजी एयरलाइंस के चार कर्मचारियों को कथित तौर पर बुरी तरह पीटने की घटना के प्रकाश में आने के बाद एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

एयरलाइंस स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर में तैनात एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने 26 जुलाई को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उसके चार कर्मचारियों पर कथित तौर पर तब हमला बोल दिया जब उन्होंने सामान के किराए के भुगतान का अनुरोध किया। इस मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज

- एयर लाइन्स के अनुसार, सेना अधिकारी के सामान का वजन अधिक था तथा उनसे बोर्डिंग गेट पर अतिरिक्त भार के भुगतान के लिए कहा गया था।
- सेना ने कहा कि वह जाँच में पूरा सहयोग करेगी।

कराई है और नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्री का नाम काली सूची (नो-फ्लाई) में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरलाइंस ने कहा कि उसने घटना का सीसीटीवी फुटेज हासिल करके पुलिस को सौंप दिया है और वह इस मामले की पूरी कानूनी और नियामकीय जाँच पर जोर देगी। प्रवक्ता ने बताया कि उक्त अधिकारी ने श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या एसजी -386 के बोर्डिंग गेट पर तैनात एयरलाइंस के

चार कर्मचारियों को इतना पीटा कि एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके जबड़े में गंभीर चोट आई। जब दूसरे कर्मचारी उसे बचाने आए तो अधिकारी ने उन्हें भी पीटा। प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारी के सामान का वजन 10 किलोग्राम था जबकि, मुसाफिरों को विमान के अंदर केवल सात किलोग्राम ले जाने की इजाजत है। प्रवक्ता ने कहा, "जब उनको विनम्रतापूर्वक इस बारे में बताया गया और लागू शुल्क का भुगतान के

लिए कहा गया, तो यात्री ने इन्कार कर दिया और बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी किए बिना ही जबरन एयरोब्रिज में प्रवेश कर गया। यह विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन था।" प्रवक्ता ने कहा, "सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने उसे वापस गेट तक पहुँचाया।" इस मामले में सेना ने कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगी। सेना ने बयान में कहा, हम अनुशासन के उच्च मानकों पर चलते हैं और इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं।

बद्रीनाथ हाईवे पर पुल क्षतिग्रस्त, भारी वाहनों पर रोक

चमोली, 03 अगस्त। उत्तराखण्ड के चमोली जिले मे शनिवार रात्रि को भारी वर्षा होने के कारण बदरीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी स्थित मोटर पुल के दोनों ओर की एबटमेंट सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है। सतकंता और सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई

- हल्के वाहनों का आवागमन चालू रखा गया है तथा बद्रीनाथ यात्री भी फिलहाल जारी है।

है। छोटे वाहनों टैक्सी, कार सहित अन्य हल्के वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। बदरीनाथ यात्रा फिलहाल जारी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जानकारी देते हुए रविवार को बताया फिलहाल बदरीनाथ हाईवे यहाँ पर हल्के वाहनों के ही खोला गया है। पांडुकेनवर से ऊपर सभी भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है।

गडकरी के घर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पुलिस और डॉंग स्कॉयड की टीम ने गडकरी के घर मेंसर्व ऑपरेशन भी चलाया।

कुछ घंटों बाद गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम उमेश विष्णु राउत है। उमेश विष्णु राउत मेडिकल चौक स्थित एक देसी शराब की दुकान पर काम करता है। पुलिस ने उसे नागपुर के बीमा दवाखाना के पास से गिरफ्तार किया है।

बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में ही मौजूद हैं। पुलिस की टीम अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर धमकी देने के पीछे की मंशा को जानना चाहेगी कि कहीं इस घटना में कोई और एंगल तो नहीं है।

सरकार ने 35 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अधिक वसूली गई राशि को वसूलना शामिल होगा। एनपीपीए ने साफ किया है कि निर्धारित मूल्यों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है, जिसे लागू होने पर जोड़ा जा सकता है। निर्माताओं को सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा, ईटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से फॉर्म वी में अपडेटेड प्राइस लिस्ट जारी करनी होगी और एनपीपीए तथा राज्य औषधि नियंत्रकों को जानकारी देनी होगी। स्पेसिफाइड फॉर्मूलेशन और निर्माताओं के लिए जारी किए गए किसी भी पूर्व मूल्य आदेश को इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की संभावना

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है

रायपुर, 03 अगस्त। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तथा पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को आशंका है कि उन्हें शराब,कोयला और महादेव सट्टा एप घोटालों में नाम आने के बाद कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

इस गिरफ्तारी से बचने के लिए बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और न्यायालय सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए विचार कर सकता है।

बघेल ने याचिका में मांग की है कि उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्रष्टे के चलते की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है

- शराब, कोयला तथा महादेव सट्टा घोटाले में सीबीआई और ईडी की जाँच के बाद उनके पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य व केन्द्र की जाँच एजेंसियों ने कुछ समय पूर्व संबंधित मामलों की जाँच की गति तेज कर दी है।

कि, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। यह याचिका ऐसे समय में दाखिल की गई है जब राज्य और केन्द्र की जांच एजेंसियों, ईडी तथा आर्थिक अपराध शाखा सहित कई केन्द्रीय जांच एजेंसियों ने संबंधित मामलों की जांच तेज कर दी है।

यह याचिका सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लिस्टिंग की गई है। इसके अलावा बघेल और उनके बेटे ने सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही जांचों की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि सीबीआई और ईडी

को छत्तीसगढ़ में जांच करने का अधिकार किस आधार पर मिला, जब राज्य सरकार ने पहले ही उनकी आम सहमति वापस ले ली थी।

सितंबर से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) 12 के अनुसार हर साल रजिस्टर्ड पोस्ट की संख्या में गिरावट आ रही है। साल 2011-12 में रजिस्टर्ड डाक से भेजने वाले आर्टिकल 24 करोड़ से घटकर 2019-20 में 18 करोड़ के रह गए। 25 फीसदी की कमी साफ देखी जा सकती है। कोरोना के बाद से तो स्थिति और खराब हो गई है।

‘योगी के कैबिनेट मंत्री राजभर बिहार में भाजपा पर दबाव बना रहे हैं’

वे बिहार विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटों पर गठबंधन करना चाहते हैं

लखनऊ, 3 अगस्त। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब नए समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके संकेत उस समय मिलने शुरू हो गए जब उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो सारे विकल्प खुले हुए हैं।

दरअसल, भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार चुनाव लड़ने के लिए गैर-भाजपा दलों के साथ तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत

- राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी कई वर्षों से बिहार में सक्रिय है, इसलिए वे विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं।

देकर अपनी राजनीतिक ताकत फिर से दिखानी शुरू कर दी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में कहा अगर बिहार में भाजपा के साथ हमारा गठबंधन नहीं होता है, तो हम सभी विकल्प खुले रखेंगे।

योगी सरकार में मंत्री राजभर ने

कहा कि उनकी पार्टी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में एकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) सहित कई छोटी पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है।

राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कम से कम 156 पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा यह

सब इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति क्या और कैसी बनती है। हम बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, जहां हम पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं।

भाजपा के सूत्रों ने बताया कि राजभर सीवान, चंपारण, सारण, गोपालगंज और बक्सर के कुछ इलाकों में सम्मानजनक सीटों के लिए भाजपा से कड़ी मोलभाव कर रहे हैं जहां राजभर, राजवंशी, राजघोषी और भर समुदायों की अच्छी-खासी मौजूदगी है। पार्टी का लक्ष्य पटवा और मंडल जैसी जातियों को भी एकजुट करना है।

एयर इंडिया का पुनः “राष्ट्रीयकरण” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विमान ऑर्डर दिया है, तकनीक और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश किया है, और ब्रांड की साख वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का बदलाव, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भी, कई सालों में होता है, महीनों में नहीं।

आज जो समस्याएँ एयर इंडिया में देखी जा रही हैं, वे पुनर्गठन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, न कि व्यवस्था की विफलता। अभी अगर फिर से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो भारत के आर्थिक सुधारों की साख को बड़ा झटका लगेगा और वैश्विक निवेशकों का भरोसा कमजोर होगा, जिन्हें नीति में स्थिरता चाहिए।

यह बात सही है कि एयर इंडिया के साथ भावनात्मक लगाव आज भी बना हुआ है। दशकों तक यह भारत की हवाई

- पर, यह भी जरूरी है कि एयर इंडिया का मैनेजमेंट अपनी दिक्कतों व कमियों के बारे में सही जानकारी दे जनता को, नहीं तो यह “इम्पेशन” जोर पकड़ लेगा कि मैनेजमेंट के पास सिविल एविएशन का पूरा अनुभव नहीं है और कार्य कुशलता के अभाव में कंपनी डूब जायेगी।

पहचान रह गई, प्रधानमंत्रियों को ले जाने वाली, संकेत में नागरिकों को वापस लाने वाली और प्रवासि भारतीयों को देश से जोड़ने वाली एयरलाइन। जब वही एयरलाइन निजी हाथों में संघर्ष करती दिखती है, तो लोगों को पीड़ा होती है।

अगर टाटा समूह द्वारा दी जा रही पूंजी और स्वतंत्रता के बावजूद एयरलाइन लगातार विफल होती है, तो सार्वजनिक हित की बात फिर से उठ सकती है। मनीष तिवारी की यह चिंता, कि गैर-विमानन पेशेवर (नॉन

एविएशन प्रॉफेशनल्स) से चला रहा है, इस बड़े भय को दर्शाती है कि एयर इंडिया की आत्मा सिर्फ लाभ कमाने के चक्कर में कहीं खो रही है।

इसके अलावा, भारत जैसे विशाल देश में हवाई संयोजक एक रणनीतिक संसाधन है। अगर निजी नियंत्रण में कुछ प्रमुख मार्ग घाटे का सौदा बनते हैं, तो जनता की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। ऐसे में सरकार को सीधे या रैग्युलेशन के जरिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।

फिर भी, एयर इंडिया का पुनः राष्ट्रीयकरण अभी जल्दबाजी होगी और

मुश्किल से हो रहे सुधारों को कमजोर करने का खतरा पैदा हो सकता है। एयर इंडिया को कब्जे में लेने की नहीं, बल्कि कड़ी निगरानी की जरूरत है। सरकार को अपने नियामक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सेवा गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा पर नजर रखनी चाहिए। वहीं, टाटा समूह को संवाद बेहतर करना होगा, तेजी से कदम उठाने होंगे और यात्रियों व नीति-निर्माताओं, दोनों को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे इस जिम्मेदारी के लायक हैं।

निजीकरण कभी कोई जादू की छड़ी नहीं था। यह एक ऐसा कदम था, जिससे सरकार को एयरलाइन चलाने के काम से आज़ाद किया जा सके, ताकि वह शासन पर ध्यान दे सके। ईसी भावना में, जरूरी है कि जो टूटा है, उसे ठीक किया जाए, बिना उसे फिर से पूरी तरह बिगाड़े।